RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 2021; 6(5):174-178
ISSN: 2455-3085 (Online)
https://doi.org/10.31305/rrijm.2021.v06.i05.025
Double Blind Peer Reviewed/Refereed Journal
https://www.rrjournals.com/

Research Paper

वर्तमान परिदृश्य में भारत नेपाल संबंधों का बदलता स्वरूप : सामान्य विश्लेषण

अनिल कुमार सरोवा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चुरु (राज.)

ABSTRACT

कोरोना काल में नेपाल की तराई के व्यापार को बहुत बड़ा झटका लगा है। सीमा सील होने के कारण नेपाल की तराई व नेपाल के पर्यटन पर जाने वाले भारतीयों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। कोरोना के साथ लिपुलेख, कालापानी विवाद ने नेपाल के प्रति भारतीयों की हमदर्दी भी कम हो गई है। यही कारण है नेपाल का पर्यटन उद्योग चौपट हो गया है और नेपाल की तराई के शहर व बाजारों से भी रौनक गायब हो गई है। भारत से जुड़ी नेपाल की लंबी सीमा में बिहार, उत्तर प्रदेश से सटे जिलों के लोगों से नेपाल की तराई के बाजारों में जो रौनक थी वह गायब हो चुकी है। भारतीय सीमा से जुड़े नेपाली बाजार में 80 प्रतिशत की खरीदारी भारतीय करते रहे। नेपाल की तराई में बसे मधेशी भारतीय मूल के नेपाली हैं और उनका समर्थन आज भी भारत के साथ है। नेपाल का हजारों करोड़ का व्यापार व पर्यटन भारतीयों के पैसे जीवित है। भारत नेपाल सीमा कोरोना को देखते हुए सील है। सिर्फ जिन्हें अनुमति मिली है, उन्हें ही प्रवेश मिल पा रहा है। इस बीच विवादित नक्शे को लेकर भी गतिरोध बरकरार है। दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों पर इसका असर दिखा है। ज्यादा प्रभाव इन दिनों खुदरा व्यापार पर पड़ा है। क्योंकि भारत एवं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के ज्यादा लोग जरूरत की छोटी मोटी सामग्री की खरीदारी सीमा से लगे बाजारों से करते हैं। लेकिन हालात बदले तो सब कुछ ठप हो गया। करोड़ों का खुदरा व्यापार प्रभावित हुआ है। भारत और नेपाल दोनों देशों के सीमावर्ती बाजारों की रौनक समाप्त हो गई हैं। महराजगंज जिले से सटे नौतनवां, सोनौली, टूठीबारी, बरगदवा, कोल्हुई, भगवानपुर और नेपाल के दो जिला रूपनदेही, नवलपरासी से भैरहवां और बुटवल का बाजार, बेलहिया बाजार, महेशपुर, सिद्धार्थनगर व बलरामपुर से सटे कृष्णानगर, बहराइच से सटे बांके जिला नेपालगंज में तीन महीने के भीतर करोड़ों का खुदरा कारोबार प्रभावित हुआ है।

Keywords: *सीमावर्ती, लिपुलेख, धार–चूला, कालापानी, पारगमन, शरणार्थियो, आई.एस.आई.*

Article Publication

Published Online: 15-May-2021

***Author's Correspondence**

अनिल कुमार सरोवा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चुरु (राज.)

sarowaanil[at]gmail.com

© 2021The Authors. Published by *Research Review Journals*

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

प्रस्तावना–

भारत नेपाल सम्बन्धों में नवम्बर–1994 में एक नया मोड़ आया जब कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी नेपाल के प्रधानमंत्री बने, तब यह आशंका व्यक्त की जाने लगी कि भारत–नेपाल सम्बन्धों की मधुरता कम होगी लेकिन फरवरी, 1995 में भारत यात्रा के दौरान मनमोहन अधिकारी ने परिस्थितियों में बदलाव और संधि की कुछ आपत्तिजनक व्यवस्थाओं के कारण भारत–नेपाल संधि 1950 में संशोधन की मांग की। परिणामतः इस पर भविष्य में बात–चीत के लिए सहमति बनी। इसके अतिरिक्त नेपाल मे भूटान शरणार्थियों के विषय में, भारत के व्यवसायियों को नेपाल में पूंजीनिवेश के बारे में आश्वासन दिये गये। संयुक्त विज्ञप्ति में यह घोषणा की गई कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की सुरक्षा के लिए खतरनाक कार्यवाहियों को अपनी जमीन पर नही होने देगा। इस तरह मनमोहन अधिकारी को भारत विरोधी होने की पूर्व भ्रांति का खण्डन हुआ।[1]

भारत नेपाल सम्बन्धों को सुधारने के लिए 1995 में जब शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने तो भारत के साथ पानी तथा विद्युत सहित कई लम्बित पडी योजनाओं के सम्बन्ध में ऐतिहासिक समझौता किये। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी सन–1996 में नेपाल यात्रा पर गये और जलसंसाधन और विद्युत ऊर्जा को विषय पर उलझे मामलों को सुलझाया और भारत–नेपाल संधि–1950 के बारे में भी स्पष्ट कर दिया कि इस संधि में संशोधन करने का कोई प्रावधान नही है, केवल इसे समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भारत के स्पष्ट वक्तव्यों, साफ इरादों और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों से दोनों देशों के बीच गलतफहमिया तो दूर हुई ही साथ ही मधुर सम्बन्ध भी विकसित हुए।

शोध विस्तार –

भारत–नेपाल सम्बन्धों को मधुर और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ करने हेतु 1998–99 में नेपाल की महाकाली परियोजना के साथ–साथ नेपाल के आयात–निर्यात को सुगम बनाने के लिए उसे पारगमन अधिकार दिये गये तथा जो पारगमन संधि की अवधि 5 दिसम्बर 1998 को समाप्त हो गई थी, उस पर 5 जनवरी 1999 को दोनो देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने हस्ताक्षर कर उसे 5 जनवरी 2005 तक के लिए बढ़ा दिया। इस कड़ी में भारत नेपाल सीमा पर स्थित नो मेन्स लैण्ड पर बढ़ रहे अतिक्रमण एवं अपराध और दूसरे देशों में पलायन को रोकने के लिए दोनों देशों ने संयुक्त प्रयास किये जिसका सार्थक परिणाम रहा।

2001 में राजमहल की क्रांति के दौरान राजपरिवार के सदस्यों की हत्या और ज्ञानेन्द्र के नेपाल नरेश होने की घटना के समय भारत नेपाल सम्बन्धों में कुछ तनाव आने की गुंजाइश थी, क्योंकि नेपाल के कुछ राजनीतिक दल और संगठन भारत की ओर भी संकेत कर रहे थे, लेकिन दोनों देशों की सरकारों ने संयम से काम किया और 183 सरकारी स्तर पर एक दूसरे के विरूद्ध कोई भी आरोप–प्रत्यारोप नहीं हुये। इसी दौरान भारत और नेपाल के गृह सचिव के बीच हुई त्रिदिवसीय वार्ता मे भारत व नेपाल के बीच 1800 किलोमीटर की सीमा पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी कदम उठाने पर सहमति हुई। इन समस्याओं में आतंकवादियों को सीमा पार करने से रोकना तथा तस्करी व नशीली दवाओं को लाने पर निगाह रखना शामिल है। यह भी एक सुपरिचित तथ्य है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई०एस.आई0 ने नेपाल में अपना जाल फैला रखा है और वहाँ वे भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन करते है। बात–चीत में नेपाल के प्रतिनिधिमण्डल ने अपने देश में माओवादी उग्रपंथियों की बढ़ती हुई गतिविधियों से भारत को अवगत कराया। दरअसल दोनों देशों की सुरक्षा को खतरा पैदा करने की चेष्टाएं हो रही है, इसलिए भारत व नेपाल में अधिकारी स्तर पर घनिष्ठ तालमेल व सम्पर्क आवश्यक है। दोनों देशों की लम्बी सीमा पर जो प्रवेश व निकास के रास्ते हैं, उन्हें और युक्तिसंगत बनाने पर भी विचार–विमर्श हुआ। साथ ही दोनों देशों के बीच पुलिस बल और नागरिक सुरक्षा से सम्बद्ध अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति हुई।[2]

सितम्बर, 2008 में नेपाल के नवनिर्वाचित माओवादी प्रधानमंत्री प्रचंड (पुष्प कमल दहल) भारत के यात्रा पर आये और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी, विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी वं यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ उनकी अलग–अलग वार्तायें हुई। इस दौरान 1950 की भारत व नेपाल संधि का मुद्दा प्रमुख रहा। इसके अतिरिक्त 1964 के कोसी नदी समझौता पर भी गम्भीर चर्चा हुई। प्रधान मंत्री की वार्ता के पश्चात जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि नेपाल व भारत आपसी सम्बन्धों को और अधिक मजबूत बनायेगें तथा नेपाल मे आधारिक संरचना के विकास व औद्योगीकरण हेतु भारत मदद करेगा। तत्कालिक सहायता के तौर पर गेहूँ, चावल, चीनी व मक्का आदि जरूरी फसलों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध पर नेपाल के लिये छूट दी जायेगी। इस क्रम में भारत–नेपाल मधुर सम्बन्ध को कायम रखने तथा नेपाल के आर्थिक विकास में सहयोग देने हेतु भारत के उद्यमियों ने नेपाल की मदद के लिए पर्यटन, कृषि एवं आधारिक संरचना के क्षेत्र में निवेश पर जोर दिया। भारत नेपाल सम्बन्धों को मधुरता प्रदान करने के लिए अक्टूबर–2011 के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री डॉ बाबूराम भट्टाराई एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ भारत की यात्रा पर आये। इस यात्रा के दौरान भारत ने एक एमीनेन्ट पर्सन्स ग्रुप स्थापित करने पर सहमति दी जो नेपाल सम्बन्धों को मजबूत एवं विस्तारित करने के उपाय सुझाये। दोनों देशो के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में भारत–नेपाल द्वितीय निवेश प्रोटेक्शन एवं संवर्द्धन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। इस क्रम में भारत द्वारा नेपाल के आर्थिक विकास में सहयोग करने तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में विकास की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से नेपाल को भारत से जुड़े उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में समेकित चेक पोस्टों के विकास, क्रास बार्डर, रेल लिंक तथा तराई क्षेत्र में फीडर रोड तथा पार्श्विक सड़कों के विकास के जरिये आधारभूत संरचना का विकास करने में सहायता देने की बात की गयी। साथ ही नेपाल में व्यापार को बढ़ावा देने से पनबिजली, कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढ़ाचा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी लाभ के लिए भारतीय निवेश के प्रमुख विस्तार की सम्भावनाओं को देखते हुए नेपाल में स्थापित करने एवं उसके सहयोग करने की बात प्रमुख रही।[3]

नेपाल को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न एवं राजनीतिक–सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अगस्त–2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर गये और वहाँ के राष्ट्रपति श्री रामबरन यादव, प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला, संविधान सभा के अध्यक्ष एवं विदेश मंत्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेय और व्यवसायिक समुदाय एवं राजनीतिक दलों से बातचीत की। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस दौरान नेपाल को आर्थिक सहायता देने और सम्बन्ध मजबूत करने की बात की। तथा अपने सम्बोधन भाषण मे कहा कि नेपाल सीता और जनक की भूमि है, इसका भारत से सम्बन्ध हिमालय और गंगा जितने पुराने है। इस प्रकार नेपाल के प्राचीन सम्बन्धों की तरफ इशारा किया। इस क्रम में उन्होनें कहा कि मेरी यात्रा हमारी प्रकृति, इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म की साझा विरासत को प्रदर्शित करती है। यह यात्रा नेपाल के साथ हमारे सम्बन्धों को एक नये स्तर पर ले जाने के निश्चय को उजागर करती है। इस दौरान दोनों देश के बीच व्यापार और निवेश, जल–विद्युत, कृषि–प्रसंस्करण, पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति सहित प्रमुख क्षेत्रों में

अपने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए नेपाली नेतृत्व और व्यवसायिक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साथ ही नेपाल पर्यटन विकास, नेपाल में गोइत्रे नियन्त्रण कार्यक्रम एवं सरकारी नियंत्रण वाले टीवी चैनल दूरदर्शन और नेपाल टेलीविजन के बीच परस्पर सहयोग सम्बन्धी सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर भी किये गये। भारत की तरफ से नेपाल के लिए सड़क और जलविद्युत हेतु एक अरब डालर अनुदान के रूप में भी दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल के प्रति उदारता और अपनत्व को देखते हुए नेपाल के विदेश मंत्री ने अपने सम्बोधन भाषण में कहा कि मोदी परिणामोन्मुखी व्यक्ति है, और वह आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता देते है। वह नेपाल के साथ सम्बन्ध मजबूत करना चाहते है। इस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री की यह नेपाल यात्रा विकास और दोनों देशों के बीच एक नयी शुरूआत पर केन्द्रित रही साथ ही यह उम्मीद जतायी गयी की भारत नेपाल सम्बन्ध दक्षिणी एशिया की साझेदारी और समृद्धि के लिए आदर्श और प्रेरक बल का काम करेगे।

अप्रैल–2015 में नेपाल में भूकम्प ने दोनों देशों के मध्य आपसी समझ एवं दोस्ती का एक नया ही रूप प्रस्तुत किया। भारत द्वारा न केवल आर्थिक रूप से नेपाल का सहयोग किया गया बल्कि सेना द्वारा राहत कार्यक्रम का संचालन कर नेपाल को पुनः भारत के साथ अपने सम्बन्धों को एक नये आयाम पर पहुंचाने की सम्भावना भी व्यक्त की गई। इसके अलावा भारत द्वारा नेपाल को इसकी नदियों पर ऊँचे बॉध बनाने के साथ–साथ गहरे जलाशयों का निर्माण करने तथा खाद्य नियन्त्रण, नौ चालन एवं उत्तर–प्रदेश, बिहार में सिंचाई एवं शहरी घटकों के प्रयोग को भी अनुमति दी है।[4]

नेपाल की राजनीतिक उथल–पुथल एवं नये संविधान की रचना में आने वाली नित नई चुनौतियों का प्रभाव न केवल इसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, बल्कि भारत–नेपाल सम्बन्धों पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। हलाँकि इस सम्बन्ध में दोनों देशों की सरकारो के द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। तथापि बदलते क्षेत्रीय सम्बन्धों में यह न तो बहुत आसान है और न ही बहुत कठिन। सम्भवतः इसका कारण यह है कि हमेशा से ही भारत नेपाल के मध्य मधुर एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध रहे है। जैसा कि हम सभी जानते है कि पिछले कुछ दिनों में भारत एवं चीन के मध्य डोकलाम मुद्दे को लेकर तनाव की स्थिति बनी। ऐसे में भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो गया है। यह तभी सम्भव है जब भारत अपनी राष्ट्रीय राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य सामंजस्य बैठाते हुए अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में गम्भीरता से विचार–विमर्श करे। वस्तुतः भारत नहीं चाहेगा कि चीन के समक्ष किसी मुद्दे पर वह अकेला पड़े इसलिए उसके पड़ोसी देशों का पर्याप्त समर्थन करने की आवश्यकता है।

भारत नेपाल सम्बन्धों को नया आयाम देने के लिए अगस्त, 2017 में नेपाल के नवनियुक्त प्रधनमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत यात्रा पर आये। यात्रा के दौरान भारतीय नेताओं के साथ पहले की योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा कुछ वर्तमान जरूरी मुद्दो पर बातचीत की। मुद्दों में मधेसी मुद्दा, न्यायाधीशों, राजपूतों एवं सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति प्रमुख रहा। हलाँकि नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान इस सम्बन्ध में बेहतर प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों को एक नये मुकाम पर पहुँचाया जा सके। ओली की चीन से नजदीकी शायद ही किसी से छिपी हो, लेकिन उसके शासन में नेपाल की आंतरिक राजनीति पर बीजिंग का प्रभाव केवल बन ही है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल की तरफ से कुर्सी से हटने की कोशिशों के बाद ओली खुद नेपाल कम्युनिस्ट पार्ट में अलग–थलग पड़ गए हैं।[5]

2016 में जब प्रचंड ने ओली को सत्ताच्युत किया था तो उस समय चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने उनकी आलोचना करते हए एक लेख में कहा था कि काठमांडू कैसे बीजिंग के साथ का मौका गंवा सकता है। इससे साफ पता चलता है कि यह देश नेपाल की घरेलू राजनीति को कैसे देखता है, सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस सबके बीच नेपाल में व्यापक स्तर पर प्रभाव बढ़ाने के लिए देश में चीन की राजदूत होउ यानकी को जरिया बनाया जा रहा है।

उसके अलावा खनाल, माधव नेपाल और बामदेव गौतम ने भी ओली पर अपने बयानों से भारत के साथ समीकरण बिगाड़ने और पार्टी को अपमानजनक स्थिति में खड़ा करने का आरोप लगाया। नेपाल के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का लेकर ओली का टकरावपूर्ण रवैया चीन के सक्रिय समर्थन के बिना संभव नहीं था। प्रो. कर्ण ने आगे कहा, 'पीएम ओली' अब भारत को नाराज करने से नहीं डरते, इस बीच उन्होंने चीनी राजदूत के साथ विचार–विमर्श किया है. पीएम ओली ने कालापानी विवाद में भी चीन की भूमिका का बचाव किया। उन्होंने तो दरअसल कई बार चीनी राजदूत के साथ विचार–विमर्श किया है।''[6]

काठमांडू स्थित थिंक–टैंक इंस्टीटयूट फार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्टडीज के सीनियर फेलो और काठमांडू पोस्ट के पूर्व मुख्य संपादक अखिलेश उपाध्याय कहते हैं, 'भारतीय सेना प्रमुख की हालिया असंवेदनशील टिप्पणी ने नेपाल को बहुत निराश किया है। इसके अलावा, नवंबर से ही नेपाल सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ एक बैठक की मांग कर रहा है। आखिरी आधिकारिक अनुरोध जनवरी में भेजा गया लेकिन नई दिल्ली ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर सभी बातों ने काठमांडू की

नाराजगी बढ़ा दी है।' उपाध्याय ने कहा, ''जहां तक चीन की बात है, इसका प्रभाव दुनियाभर में बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि वह इसे अपने आसपास तो बढ़ाएगा ही. नया चीन पुराने हिमालय को एक बाधा के रूप में नहीं देखता।''[7]

घरेलू राजनीति तो बस एक पहलू है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है कि बीजिंग आर्थिक रूप से नेपाल के लिए कितनी बड़ी जरूरत है। राजदूत होउ ने राइजिंग नेपाल को दिए साक्षात्कार में कहा, ''2019 में चीन और नेपाल के बीच व्यापार 1.5 बिलियन डालर तक पहुंच गया, लगभग 170,000 चीनी पर्यटक 2019 में नेपाल यात्रा पर आए और चीन नेपाल में दूसरा सबसे बड़ा पर्यटक स्रोत बन गया है। उन्होंने कहा, 'नेपाल की तरफ से दिए गए आंकड़ें बताते हैं कि नेपाल को कुल सहायता देने के मामले में चीन नेपाल के द्विपक्षीय विकास सहयोग भागीदारों में पहले स्थान पर है। चीन का कुल अनुदान 106 मिलियन डालर है और वह नेपाल के सभी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास सहयोग भागीदारों में पहले स्थान पर है।''[8]

होउ ने आगे कहा, ''चीन की मदद वाली 25 भूकंप–रोधी पुनर्निर्माण परियोजनाएं, काठमांडू रिंग रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का पहला चरण और काठमांडू दरबार हाई स्कूल पुनर्निर्माण परियोजना सहित 12 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं, जबकि अन्य परियोजनाएं भी व्यवस्थित और संगठित तरीके से चल रही हैं।''[9]

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना के पीछे नेपाल पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य निहित है। विशेषज्ञ बीजिंग के इस झुकाव को बड़ा दांव लगाने और भारत पर आर्थिक निर्भरता घटाने की नेपाल. की इच्छा का नतीजा भी मानते हैं। काठमांडू पोस्ट में स्तंभकार अमीश मुल्मी ने कहा ''नेपाल का उत्तर की ओर रुख करना बदलाव के दौर में नेपाल के घरेलू मामलों में भारत की तरफ से जरूरत से ज्यादा दखल, जो 2015 में नाकेबंदी के रूप में सामने आया, देने की प्रतिक्रिया है, क्योंकि भारत पर आर्थिक निर्भरता घटाने के लिए इसकी दरकार है।''[10]

मुल्मी ने कहा, ''चीन की मदद से उसे बुनियादी ढांचे के विकास के जरिये आर्थिक वृद्धि की संभावना भी नजर आती है।' इसके अलावा, चीन पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना में भी शामिल है– इसकी प्रभारी कंपनी चीन की सीएएमसी इंजीनियरिंग है, और काठमांडू ने परियोजना के वित्त पोषण के लिए मार्च 2016 में चीन के एक्जिम बैंक के साथ 215.96 मिलियन डालर का साफ्ट लोन करार भी किया था। वहीं, विनिर्माण और जलविद्युत क्षेत्रों में भी निवेश हैं, नेपाल–चीन का संयुक्त उपक्रम होंगशी–शिवम सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस हिमालयी राष्ट्र का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। पिछले साल अक्टूबर में शी जिनपिंग ने नेपाल का दौरा किया और कई निवेशों की घोषणा भी की, यह दो दशकों में किसी चीनी राष्ट्रपति का इस देश में पहला दौरा था। वित्त वर्ष 2018–19 में भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा 85,519 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि चीन के साथ यह 20,340 करोड़ रुपये रहा।''[11]

नेपाल में भारतीय दूतावास की वेबसाइट के मुताबिक, 'भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, इसके अलावा नेपाल के लगभग पूरे थर्ड कंट्री ट्रेड के लिए पारगमन सुविधा देता है। नेपाल के लिए भारत उसके दो–तिहाई से अधिक वाणिज्यिक व्यापार, सेवाओं में लगभग एक–तिहाई व्यापार, एक–तिहाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पेट्रोलियम की लगभग 100 प्रतिशत आपूर्ति, भारत में काम करने वाले श्रमिकों, पेशेवरों और पेंशनरों द्वारा वहां भेजी जाने वाली राशि के एक बड़े हिस्से के लिहाज से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।''[12]

काठमांडू निवासी एक राजनीतिक हस्ती ने नाम ने छापने की शर्त पर कहा, 'चीन नेपाल में सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों, राजनेताओं आदि के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह भी सच है कि मौजूदा चीनी राजदूत अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक सक्रियता निभाती नजर आती है। 2019–20 में चीन की तरफ से नेपाली सिविल सेवकों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम तेजी से बढ़कर 850 हो गए जिनकी संख्या 2004 में सिर्फ 20 ही थी। चीन कोविड महामारी से निपटने के उपायों को लेकर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नेपाल की मदद करता रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले महीने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी।

चीन के लिए नेपाल के साथ बढ़ती नजदीकी ने देश में निर्वासित तिब्बतियों की राजनीतिक गतिविधि का लगभग खात्मा सुनिश्चित किया है। विभिन्न सुरक्षा समझौतों और आदान–प्रदान के कारण देश में तिब्बती शरणार्थियों की आवाजाही भी उल्लेखनीय रूप से घटी है। नेपाली आव्रजन अधिकारियों के आंकड़े बताते हैं कि 2010 में 1248 की तुलना में 2015 में मात्र 85 ऐसे आवेदन आए जिसमें तिब्बतियों ने भारत जाने के लिए परमिट मांगा। नेपाल के मामलों पर नियंत्रण से बीजिंग को देश में भारतीय और पश्चिमी प्रभाव कम करने में भी मदद मिलती है। मुल्मी कहते हैं, ''दक्षिण एशिया में भारतीय प्रभाव घटाने की चीन की महत्वाकांक्षा और मौजूदा सरकार की राष्ट्रवादी, भारत विरोधी स्थिति के बीच एक समन्वय बढ़ रहा है।'' यह 2013 में शी की तरफ से शुरू की गई पड़ोस नीति से भी स्पष्ट है, जब उन्होंने कहा था, ''पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक मेलजोल दो शताब्दी के लक्ष्यों को वास्तविकता के धरातल पर लाने और चीनी राष्ट्र के अभूतपूर्व कायाकल्प का सपना पूरा करने के लिए जरूरी है।''[13]

निष्कर्ष :–

नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोईराला ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो बार नेपाल की यात्रा की। अप्रैल 2015 में नेपाल में भीषण भूकंप के बाद भारत ने नेपाल का आर्थिक, मानवीय और नैतिक समर्थन किया। भारत ने भूकंप से तबाह हो चुके नेपाल को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए एक बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता दी। दृढ़ता से यह भी कहा कि वह नेपाल सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं, जो हर नेपाली की आंख से आंसू पोंछने का प्रयास कर रही है। अपने पिछले दौरे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेपाल के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए दोनों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का वादा किया। उन्होंने संप्रभुत्ता और नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का बार–बार आश्वासन दिया। उन्होंने नेपाली जनता का दिलों दिमाग जीतने का सफलतापूर्वक प्रयास किया। साथ ही उन्होंने भार की वर्चस्ववादी छवि को दूर करने में भी काफी सहायता हासिल की।

सन्दर्भ सूची

1. जे.एन. दीक्षित : भारत की विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 61
2. राम सागर शुक्ल : अनजान पड़ोसी, भारत–नेपाल, सनातन प्रकाशन, लखनऊ, 2019, पृ. 6
3. मुकेश देवी : नेपाल–चीन के बढ़ते संबंध : भारत की सुरक्षा चिन्ता, ब्लयू रोज पब्लिर्शस, नई दिल्ली, 2017, पृ. 58
4. हिन्दुस्तान टाईम्स, 15 दिसम्बर 2011
5. दैनिक जागर, 29 अप्रैल 2015
6. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2017
7. आशीष त्रिपाठी : भारत नेपाल सम्बन्ध और दक्षेस, फर्स्ट प्रिन्ट पब्लिकेशन, जनवरी, 2017, पृ. 13
8. प्रमोद कुमार : भारत–नेपाल सम्बन्ध : चुनौतियां एवं समाधान, ए.एस.आर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2018, पृ. 84
9. वही, पृ. 15–18
10. अरूण मिश्र : भारत–नेपाल संबंध के विभिन्न आयाम, उदय पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ, 2020, पृ. 58
11. वही, पृ. 16–20
12. दैनिक जागरण, 6 दिसम्बर 2020
13. हिन्दुस्तान टाईम्स, 3 मार्च 2021